मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- बीके अस्पताल में सीटी स्कैन व एमआरआई की मारीचिका ? 3
- भाजपा ने दिखलाई राज की गुंडागर्दी दलितों की पिटाई भी की और मीटिंग भी नहीं होने दी 4
- हार्दिक पटेल की आड़ में संघ का एजेंडा 5
- मेट्रो की तारीख के नाम पर भद्दा मजाक 5
- लाल किले से बरसा मोदी का साम्प्रदायिकतावाद और जातिवाद 8

वर्ष 28 अंक 20 फरीदाबाद, मंगलवार, 1-15 सितम्बर 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

टूरिज़्म की 54 एकड़ ज़मीन पर मंत्रियों की गिद्ध-दृष्टि

हाल में अपने 'कर्मों' से परिवहन विभाग खोने वाले हरियाणा के मंत्री रामबिलास शर्मा ने राज्य टूरिज़्म का भी मन्त्री होने का लाभ उठाते हुए कापसहेड़ा (दिल्ली-गुड़गांव बार्डर पर) में अपने विभाग के दो भू-खंडों, एक 42 एकड़ का व दूसरा 12 एकड़, पर लूट का निशाना साध रखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एम्बियंस मॉल के निकट स्थित इन भू-खंडों की कीमत हज़ारों करोड़ आंकी जा रही है।

मज़दूर मोर्चा, गुड़गांव ब्यूरो

पद का नाजायज लाभ उठाते हुए रामबिलास ने 30 जुलाई 2015 को हिन्दुस्तान टाइम्स में एक विज्ञापन प्रकाशित कराया। बड़े अजीबों-ग़रीब इस विज्ञापन में इन भू-खंडों के व्यवसायिक इस्तेमाल के संभावित ग्राहकों से उनकी योजनायें मांगी गयी हैं कि इन भू-खंडों पर वे क्या-क्या कर सकते हैं और किन शर्तों पर। यानी कि होटल, रिसॉर्ट, मॉल, मनोरंजन आदि का धंधा कैसे और किन शर्तों पर करना चाहेंगे। यानी भूल-भूलैया जैसे विज्ञापन का अर्थ कुल मिलाकर यह है कि ये भू-खंड मंत्री जी अपनी 'शर्तों' पर उसे देंगे जिसे वे चाहेंगे।

रामबिलास शर्मा	कैप्टन अभिमन्यु

सब कुछ हड़पने को तैयार

विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरअसल रामबिलास ने इन ज़मीनों को हड़पने के लिये पूरी तैयारी कर ली है। इस घोटाले में अपने पैर मजबूती से जमाने के लिये उन्होंने अपने ही जैसे एक और मन्त्री कैप्टन अभिमन्यु को भी बतौर साझीदार मिला लिया है तथा वित्तीय व्यवस्था के लिये एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को भी इस षड़यन्त्र में शामिल कर लिया है।

सरकारी 'नियमानुसार' बरसों पहले स्थानीय किसानों से जन-हित के नाम पर कौड़ियों के भाव छीनी गयी इस ज़मीन पर सरकार को वही काम करना होता है जिसके लिये इसको अधिग्रहीत किया गया था। टूरिज़्म के नाम पर किसानों से झपटी गयी इस ज़मीन पर सरकार ने धनचेंरी टूरिस्ट काम्पलेक्स बनाना था, वह तो अब तक की आई गयी सरकारों से बना नहीं। किसानों को जमीन वापस लौटाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऐसे में राजनीति के हथियार से लूट-मार करने के दो माहिर खिलाड़ियों-रामबिलास व अभिमन्यु-ने उक्त योजना में हाथ मिलाया है, और तदनुसार विज्ञापन जारी किया गया है। यदि इन खिलाड़ियों की योजना सिरे चढने दी गयी तो हज़ारों करोड़ की उक्त ज़मीन ये खेल-खेल में डकार जायेंगे।

हाल में रामबिलास ने इस ज़मीन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश जारी किये। यूं इस अवसर पर खड़े-खड़े बयान जारी किये गये कि दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अति निकट एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट रिसॉर्ट तैयार किया जायेगा। इस बयान में वे इस बात का कोई उल्लेख नहीं करते कि इस रिसॉर्ट को कौन बनायेगा और पैसा कहां से आने वाला है। कयास है कि पर्दे के पीछे से दोनों मंत्री और सामने से उनका व्यवसायी मित्र ही चांदी काटेंगे।

लगता है रामविलास ने अपने हालिया अनुभवों से कोई सबक नहीं लिया है। प्रधानमंत्री मोदी तक उनकी परिवहन लूट के चर्चे पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने परिवहन महकमा उनसे ले लिया था। कहते हैं इस पर शोर-शराबा करने के एवज में मोदी ने रामबिलास को अच्छी झाड़ भी पिलाई। हालांकि हरियाणा में सभी जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ भले ही सीधी हो जाय रामबिलास का लूट-खाता बन्द नहीं कराया जा सकता। भाजपाई मन्त्री भी क्या करें! मुद्दतों बाद यह सुनहरा मौका हाथ लगा है, झोली भरने में कसर कोई भला कैसे छोड़े और किसके लिये ? कल किसने देखा है। पर जनता तो इन्हें देख ही रही है।

आरक्षण हमेशा मजबूत को ही मिलता है !

गुजरात में पटेल, महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा में जाट, राजस्थान में गूजर आरक्षणों का आन्दोलन यही तो रेखांकित करता है कि आरक्षण मजबूत को मिलता है न कि कमज़ोर को। इतिहास भी इसी समीकरण का गवाह है। क्या एक जमाने में नौकरियों, शिक्षा, व्यापार और संसाधनों का शत-प्रतिशत आरक्षण सवर्णों की मुट्ठी में ही नहीं था?

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली लागू करनी पड़ी। इसके चलते अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समुदायों को भी राजनीतिक महत्व मिलना शुरू हुआ। फ़लस्वरूप उनमें सामाजिक और आर्थिक ललक भी जागृत हुई। लिहाज़ा सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्रों में उनके लिये आरक्षण की व्यवस्था हुई। इसी तरह, समय के साथ, अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल समुदायों ने भी अपनी पिछड़ी सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति को पहचानना शुरू कर दिया। संख्याबल के दम पर उन्हें राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिलनी शुरू हो चुकी थी। अन्ततः मंडल कमीशन बनाना पड़ा और 1990 में उन्हें भी आरक्षण का लाभ देना पड़ा। यह उनके राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत होने से ही मिल पाया। इस परिप्रेक्ष्य में गुजरात के मौजूदा पटेल आरक्षण आन्दोलन को समझा जा सकता है। दो टूक बात यह कि नौजवानों को रोज़गार चाहिये परन्तु हमारी राजनीतिक सत्ता उन्हें आरक्षण के झुनझुने से बहलाती आई है। गुजरात की हिंसा बताती है कि यह रास्ता कितना खतरनाक है। सत्ता के लिये ही नहीं बेरोज़गारों के लिये भी। दरअसल बेरोज़गारों का कोई भी आन्दोलन शतप्रतिशत रोज़गार का होना चाहिये, न कि टुकड़खोर आरक्षण के लिये।

महिला थाना: छलावे को बता रहे तोहफ़ा

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 28 अगस्त को हरियाणा के प्रत्येक ज़िले की तर्ज पर यहां भी एक महिला थाना खोला गया। आधी आबादी के साथ किये गये इस छलावे को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उनके तमाम भौंपू उन्हें दिया गया एक तोहफ़ा बताते नहीं अघा रहे।

पूरे ज़िले की आबादी के लिये तो 18 थाने व 50 के करीब चौकियां ज़िले के कोने-कोने में फ़ैली हुई हैं और आधी आबादी के लिये मात्र एक थाना! यदि मोहना या धौज या पर्वतिया कॉलोनी में किसी महिला के साथ कोई वारदात होती है तो वह रात-बिरात शिकायत करने सेक्टर 16 ए तक चल कर महिला थाने पहुंचेगी अथवा अपने निकटस्थ थाने चौकी पहुंचेगी? इसके जवाब में खट्टर सरकार व उनके भौंपू कहते हैं कि पीड़ित महिला चाहे तो निकटस्थ पुलिस में जाय या महिला थाने में यह उसकी मर्ज़ी है। यह उसकी मर्ज़ी नहीं बल्कि मजबूरी होगी जो निकटता के चक्कर में केवल पुरूष थाने में जाये।

इस थाने के उद्घाटन समारोह के सारे ताम-झाम में यदि किसी ने एक भी काम की बात कही तो वह कही सीपी सुभाष यादव ने। उन्होंने अपने एसएचओ कार्यकाल का एक किस्सा सुनाया कि एक महिला उनके थाने में शिकायत लेकर आई। उसके बयान पर उन्होंने पर्चा तो दर्ज कर दिया परन्तु उन्हें तीन दिन बाद समझ आई कि पीड़िता के साथ तो बलात्कार हो चुका था। इस वारदात को वह महिला उनके सामने ठीक से वर्णन नहीं कर पाई थी। समझ आने पर बलात्कार आदि की धारायें लगा कर केस को आगे बढाया और दोषी को पूरी सज़ा कराई।

बस इसी उदाहरण को यदि खट्टर सरकार समझले तो वह हर थाने-चौकी को महिलाओं के अनुरूप बना सकती थी। हर थाने-चौकी में महिला कर्मियों की पर्याप्त संख्या हो तो महिलाओं को इधर-उधर न भटकना पड़े। सारे ज़िले की महिला कर्मियों को एक थाने में बैठाने की अपेक्षा सभी थानों में इनकी पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति होनी चाहिये। इसके लिये जरूरी है पुलिस में महिलाओं का अनुपात पुरूषों के बराबर न सही कहीं आस-पास तो हो जो कि आज मात्र साढे छह प्रतिशत ही है। इस पुरूष प्रधान महकमे में क्यों नहीं महिलाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित की जाती? क्यों नहीं पूरे महकमे को लिंग-संवेदी बनाने की ओर ध्यान दिया जाता?

हरियाणा सरकार पूरे ज़ोर से दहाड़-दहाड़ कर दावा कर रही है कि देश का एक मात्र राज्य हरियाणा है जहां हर ज़िले में महिला थाना है जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चत होगी। यह दावा पूरी तरह से हास्यास्पद है। ज़िले का एक थाना कैसे पूरे ज़िले भर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है? असंभव। रही बात बाकी राज्यों की तो वे इतने बावले नहीं हैं जो ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डेवेलेपमेंट, नेशनल पुलिस एकेडमी तथा न्यायमूर्ति वर्मा आयोग द्वारा खारिज किये जा चुके महिला थाने की अवधारणा को अपने यहां लागू करते। एकमात्र राज्य है तमिलनाडू जहां इसे बड़े पैमाने पर लागू किया गया जो पूरी तरह फ़्लॉप सिद्ध हुआ है।

यदि यह धारणा महिला सुरक्षा के लिये ज़रा भी कारगर होती तो चंडीगढ और दिल्ली कभी पीछे न रहते। इन दोनों शहरों में हर थाने को लिंग-संवेदी तथा महिला थाने जैसा बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये तमाम थानों में महिला कर्मियों की संख्या को पर्याप्त मात्रा में बढाने के प्रयास किये जा रहे हैं। आज के दिन इसका सर्वोत्तम उदाहरण केरल में देखने को मिलता है। वहां हर थाना-चौकी किसी भी महिला थाने से बेहतर है, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में महिलाकर्मी तैनात हैं।

देर-सबेर फ्लॉप तो हरियाणा के महिला थाने भी होने ही हैं क्योंकि छांयसा, तिगांव व धौज से तो क्या एक नम्बर व सराय से भी कोई पीड़िता यहां आने वाली नहीं। इस थाने के मुहुर्त काल में सामूहिक बलात्कार का जो पर्चा दर्ज हुआ है वह भी थाना 55 से जबरन यहां भेजा गया है। अब देखना यह है कि इस थाने को चलाने के लिये कब तक पीड़िताओं को यहां जबरन भेजा जा सकेगा। हरियाणा का सबसे पहला महिला थाना करीब 20 वर्ष पूर्व सोनीपत में बना था जहां किसी भी साल 50-55 से अधिक पर्चे दर्ज नहीं हुए। इतने कम पर्चे जहां हों उसे फ़्लॉप ही कहते हैं।

ख़बर दार

महिला पुलिस थाना-किसके लिये

हरियाणा के हर ज़िले में महिला पुलिस थाना खोले जाने की श्रंखला में फ़रीदाबाद के सेक्टर 16-ए में 28 अगस्त को ऐसा ही एक थाना खोला गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसे प्रदेश की महिलाओं के लिये एक नायाब तोहफ़ा बता रहे हैं। उनका दावा है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा बेहतर होगी और उन्हें पुलिस से अपनी परेशानियां दूर कराने में सुविधा महसूस होगी। इन दावों की जांच के लिये मज़दूर मोर्चा ने मुख्यमंत्री खट्टर का एक काल्पनिक साक्षात्कार लिया।

म.मो-पूरे ज़िले में केवल एक ही महिला थाना सुविधाजनक कैसे होगा? दूर-दराज़ की महिलाओं को भी यदि इसी थाने में आना पड़ेगा तो क्या वे ज़्यादा तंग नहीं होंगी?

खट्टर-यह पहलू तो हमने सोचा ही नहीं था। अब तो यही करना पड़ेगा कि महिलायें अपने-अपने क्षेत्र के थानों में पहले की तरह जाती रहें। जिसका दिल करे, महिला थाने में भी आ जाये।

म.मो.-तो क्या आप सभी थानों में पर्याप्त संख्या में महिलाकर्मी तैनात करेंगे ताकि वहां आने वाली महिलाओं को अपनी बात कहने में कोई हिचक न हो?

खट्टर-अरे, हमने तो यह भी नहीं सोचा। हमने तो सारी महिलाकर्मी महिला थानों में ही लगा दीं। खैर, अब एक-एक, दो-दो और थानों में भी भिजवा देंगे।

म.मो.-यानी जहां महिलायें जायेंगी वहां महिलाकर्मी नहीं होगी और जहां महिलाकर्मी होंगी वहां महिलाओं को आने में घोर असुविधा होगी।

खट्टर-भई क्या करें! हमें तो बताया गया था कि महिला थाना बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा अपने आप बढ़ जायेंगी।

म.मो.-अगर राह चलते महिला के साथ कोई वारदात हो जाये तो क्या वह दूर स्थित महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज करायेगी या निकट ही स्थित पुलिस चौकी या पीसीआर को अपनी व्यथा सुनायेगी?

खट्टर-भई कितनी बार कहें कि ये सारे पहलू न तो हमारे दिमाग़ में आये और न ही किसी सलाहकार ने बताये। जाहिर है विपत्ति पड़ने पर कोई भी महिला निकटतम पुलिस के पास ही जायेगी।

म.मो.-तो क्या आपने अपने सभी पुलिस वालों को लिंग-संवेदी होने का प्रशिक्षण दे रखा है? क्योंकि पुलिस के विरुद्ध महिलाओं से दुर्व्यवहार की शिकायतें आम हैं।

खट्टर-पुलिस तो बहुत दूर की बात है, हमारी पार्टी वाले और खास तौर पर संघी पृष्ठभूमि वाले भी लिंग-संवेदी नहीं हैं। वे महिलाओं के पहनावे और उनकी आज़ादी को लेकर पुलिस वालों की तरह ही टिप्पणियां करते रहते हैं। कृषिमंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने बिहार से सस्ती दुलहनें लाने का चुनावी जुमला उछाला था। इसी तरह हमारे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कह डाला कि दुपट्टा न ओढने से लड़कियों की छेड़छाड़ होती है। ऐसे में पुलिस को कहां से संवेदी बनाऊं?

म.मो.-फ़िर तो महिलायें भगवान भरोसे ही हैं? महिला थाने का आडम्बर करने से पहले आपको अन्य राज्यों का अध्ययन नहीं कर लेना चाहिये था?

खट्टर-भाई मेरे, अध्ययन ही मुझे करना होता तो मैं भला हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता?